



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208 ]  
No. 208]नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2002/श्रावण 23, 1924  
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2002/SRAVANA 23, 1924

वाणिज्य मंत्रालय

जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2002

विषय : अमरीका और कनाडा मूल के अथवा वहां से निर्यातित विटामिन-सी के आयात से संबंधी पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

सं. 14/25/2002-डीजीएडी.— साराभाई एम. कैमिकल्स ने 1995 में यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष अमरीका और कनाडा मूल के अथवा वहां से निर्यातित विटामिन सी के पाटन का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है और इस संबंध में पाटनरोधी जांच तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

1. **शामिल उत्पाद:** वर्तमान मामले में जांचाधीन उत्पाद अमरीका और कनाडा मूल का अथवा वहां से निर्यातित विटामिन सी है। विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी की तकनीकी विनिर्दिष्टताएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे पी बी 93/यू एस पी 23 और टाइप ए कोटेड आधारित हैं। विटामिन सी एक कार्बनिक रसायन है और यह सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत है।
2. विटामिन सी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के सीमा शुल्क उपशीर्ष सं.2936.27 और भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत वस्तु वर्णन एवं कोडिंग प्रणाली पर आधारित) के अंतर्गत सं.2936.27 के तहत वर्गीकृत है। तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के कार्य क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।
3. **चरेलू उद्योग की स्थिति:** मै. साराभाई एम. कैमिकल्स विटामिन सी का एक उत्पादक है और याचिकाकर्ता है जो कुल भारतीय उत्पादन के लगभग 73 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। मै. अमोली आर्गेनिक्स जो देश में विटामिन सी का उत्पादन करने वाला दूसरा एक नया सदस्य है। मै. जयंत विटामिन लि. ने बहुत पहले उत्पादन करना बन्द कर दिया है।

याचिकाकर्ता इस देश में विटामिन सी के भारतीय उत्पादन के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और वह वर्तमान याचिका दायर करने की स्थिति में है।

4. **शामिल देश:** वर्तमान जांच में अमरीका और कनाडा (जिन्हें इसमें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) शामिल हैं। यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने चीन ताईपेई (ताईवान) को शामिल किया है किन्तु यह मालूम होता है कि जांच अवधि के दौरान आयातों की मात्रा अधिकतम स्तर से कम है और इसलिए इसे इस जांच के कार्य क्षेत्र से अलग किया जाता है।
5. **समान वस्तु:** याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित माल, संबद्ध देशों के मूल के या वहां से निर्यातित माल के समान वस्तु है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित माल को उपरोक्त नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है।
6. **पाटनरोधी और पाटन मार्जिन:**

**सामान्य मूल्य:** याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उस कीमत के साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे जिस कीमत पर अमरीका और कनाडा के घरेलू बाजार में उत्पादकों/व्यापारियों द्वारा सामग्री बेची जा रही है। उन्होंने अमरीका में कंपनी के विभिन्न रसायनों जिसमें एस्कोर्बिक एसिड अर्थात् विटामिन सी भी शामिल है, की एक कीमत सूची प्राप्त की है। यह बात नोट की जाती है कि विटामिन सी के लिए निर्यातक द्वारा दर्शायी गयी कीमतें विभिन्न ग्रेडों और विभिन्न पैकिंग के लिए है। तथापि, विभिन्न ग्रेडों की कीमतों में बहुत कम अंतर है। अतः कीमत सूची के अनुसार इस कीमत को अमरीका के घरेलू बाजार विटामिन सी की सामान्य कीमत माना जा सकता है।

जहां तक कनाडा का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि कनाडा उसी क्षेत्र/महाद्वीप में है। कनाडा और अमरीका के बीच सीमा शुल्क की कोई बाधा नहीं है। कनाडा के घरेलू बाजार में जो कीमतें हैं वे अमरीका के घरेलू बाजार की कीमतों से भिन्न नहीं होंगी। इसलिए अमरीका के घरेलू बाजार की कीमतों को कनाडा के घरेलू बाजार की कीमतें भी माना जा सकता है।

**निर्यात कीमत** याचिकाकर्ताओं ने वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), कलकत्ता के नवीनतम उपलब्ध आयात आंकड़े प्रदान किए हैं और प्राधिकारी से इन आंकड़ों पर विश्वास करने का अनुरोध किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय परिवहन और पत्तन व्ययों को शामिल करके निर्यात कीमत का समायोजन करने का दावा किया है।

इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों के विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य उस कीमत से काफी अधिक है जिस कीमत पर भारत को निर्यात किया जा रहा है और अमरीका और कनाडा के निर्यातक भारत में संबद्ध माल का पाटन कर रहे हैं।

सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, पाटन मार्जिन न्यूनतम अंतिम सीमा से काफी अधिक है।

7. **क्षति एवं कारणात्मक संबंध:** घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले क्षति से संबंधित विभिन्न आर्थिक सूचक जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार में हिस्सा, बिक्री मात्रा, लाभप्रदता, कीमत कटौती, कीमत ह्रास/कमी, आदि सामूहिक और संचयी रूप से यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को

क्षति हुई है। इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

8. **पाटनरोधी जांच की शुरुआत:** उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं।
9. **जांच की अवधि:** वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2002 (12 महीने) तक है।
10. **सूचना देना:** इस जांच से संबंधित समझे जाने वाले संबद्ध देश/क्षेत्र के निर्यातकों और भारत के आयातकों को अलग अलग पत्र लिखे जा रहे हैं कि वे निम्नलिखित पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करें तथा अपने विचारों से निर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को अवगत कराएं। अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकता है।
11. **समय सीमा** वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी।
12. पाटनरोधी जांच एक समयबद्ध कार्य होने के कारण, निर्दिष्ट प्राधिकारी यदि निर्धारित समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं करता है अथवा सूचना किसी तरह से अधूरी है तो वह उपरोक्त नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकता है।
13. **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण:** नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय रूपान्तर रखे गए हैं।
14. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना नहीं देता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में पर्याप्त बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है।

**MINISTRY OF COMMERCE****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th August, 2002

**Subject : Initiation of anti-dumping investigations concerning import of Vitamin-C originating in or exported from USA and Canada.**

No. 14/25/2002-DGAD.— M/s. Sarabhai M. Chemicals has filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 alleging dumping of Vitamin 'C' originating in or exported from USA & Canada and have requested for initiation of anti dumping investigations and levy of anti-dumping duty.

1. Product Involved: The product under investigation in the present case is Vitamin 'C' originating in or exported from USA and Canada. Vitamin 'C' is also known as Ascorbic Acid. The technical specifications of Vitamin 'C' are based on National and International standards such as PB93/USP23 and type 'A' coated. Vitamin 'C' is an organic chemical and is classified under Chapter 29 of Customs Tariff Act.
2. Vitamin 'C' is classified under Customs sub-heading no.2936.27 of the Customs Tariff Act, 1975 and under no. 2936.27.00 under Indian Trade Classification (based on Harmonized Commodity Description and Coding System). The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations.
3. Domestic Industry Standing: M/s. Sarabhai M.Chemicals is a producer of Vitamin 'C' and is petitioner who represent about 73 percent of the total Indian production. M/s. Amoli Organics, a new entrants is other producer of Vitamin 'C' in the country. M/s. Jayant Vitamin Ltd. has suspended production long ago.

The petitioners represent a major proportion of the indian production of Vitamin 'C' in the country and thus have the standing to file the present petition.

4. Country(ies) Involved: The countries involved in the present investigations are USA and Canada (referred to as subject countries hereinafter). Though the petitioners included Chinese Taipei(Taiwan) in the petition, it is observed that the volume of imports during the period of investigation is lower than de minimus level and hence excluded from the purview of this investigation.
5. Like Article: The petitioner has claimed that goods produced by it are like articles to the goods originating in or exported from the subject countries. Goods produced by the petitioner are being treated as Like Articles to the goods imported from the subject countries within the meaning of the Rules.
6. Dumping and Dumping Margin:

Normal Value :Petitioners have stated that efforts were made to get evidence of the price at which the material is being sold by the producers/traders in domestic market of USA and Canada. They have been able to get a price list for various chemicals of a company in USA, which includes ascorbic acid, i.e. Vitamin C also. It is noted that the prices shown by the exporter for Vitamin C are for various grades and various packing. However, there is very little difference in prices of various grades. Therefore, the price as per the price list can be considered as the normal value of Vitamin C in domestic market of USA.

With regard to Canada, the Petitioners have submitted that Canada is in the same region/continent. There are no customs barrier between Canada and USA. The prices in domestic market of Canada would not be different than the domestic market of USA. Hence, the prices in domestic market of USA can be considered as prices in domestic market of Canada also.

Export Price: The petitioners have provided the import data as per Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI &S), Calcutta latest available and have requested the Authority to rely on the same. Adjustments have been claimed from the export price on account of Ocean Freight, Marine Insurance, Commission, Inland Transportation and Port Expenses.

There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the product under consideration in the subject countries and is significantly higher than the price at which it has been exported to India, and that the exporters from USA and Canada are dumping the subject goods in India.

Considering the normal value and export price, the dumping margins are significantly higher than the de-minimis limits.

7. Injury and Causal Link: The various economic indicators relating to injury affecting the domestic Industry such as production, capacity utilisation, market share, sales volume, profitability, price undercutting, price suppression/depression, etc. collectively and cumulatively, indicate that the domestic Industry has suffered injury. There is sufficient prima facie evidence that the import of product under consideration have caused material injury to the domestic industry.
8. Initiation of Anti-Dumping Investigation: In view of the foregoing, the Designated Authority initiates anti-dumping investigations to determine the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.
9. Period of Investigation: The period of investigation for the purpose of the present investigations is 1<sup>st</sup> April, 2001- 31<sup>st</sup> March, 2002 ( 12 months).
10. Submission of Information: The exporters in the subject countries and the importers in India known to the concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Ministry of Commerce, Directorate General of Anti dumping and Allied Duties, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
11. Time Limit: Any information relating to the present investigations should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days from the date of letter addressed to them separately.

12. Anti-dumping investigations being a time bound exercise, the Designated Authority may record its findings on the basis of facts available on record in accordance with the Rules supra, if no response is received within the time stipulated or the information is incomplete in any respect.
13. Inspection of Public File: In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.
14. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

, L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

